

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैशिक आतंकवाद को प्रभाव का विश्लेषण

डॉ उमारतन यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर—अर्थशास्त्र विभाग,
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय (झाँसी)

शोध सारांश

आतंकवाद आज विश्व के हर कोने में फैला हुआ है। खासकर भारत पिछले कई सालों से आतंकवाद के चपेट में है— एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में से एक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, पाकिस्तान के लक्षकर ए तैयबा व जैश ए मोहम्मद और बांग्लादेश के हरकतउल जिहाद आई इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों से लगातार खतरा झोल रहा है। इसके अलावा भारत की कानून और प्रवर्तन प्रणालियां बहुत पुरानी हैं, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गतिरोध पैदा होता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर स्थित ब्लूचिस्तान और अन्य भाग अलकायदा आतंकवादियों, अफगान विद्राहियों और अन्य भाग आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। भारत में आतंकवाद का सम्बन्ध क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, जो क्षेत्र आज आतंकवादी गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं उनमें जम्मू कश्मीर, मुम्बई, मध्य भारत (नक्सलवाद) और सात बहन राज्य (उत्तर पूर्व के सात राज्य) (स्वतन्त्रता और स्वायत्ता के मामले में) शामिल हैं अतीत में पंजाब में पनपे उग्रवाद में आतंकवादी गतिविधियां शामिल हो गयीं जो भारत देश के पंजाब राज्य और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई थीं। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

Keywords : आतंकवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था, विचारधारा, विकासोन्मुखी कार्य, आर्थिक नीतियाँ

आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने कुत्सित एवं निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहता है और जब ये विचार उसके पूरे नहीं होते तो वह अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए शक्ति, अस्त्रों—शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग किसी दल, समुदाय, वर्ग सम्प्रदाय आदि को भयभीत करके अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति गैरकानूनी ढंग से अथवा हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने या शासन तंत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। या यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए उचित—अनुचित माँग मनवाने के लिए हिंसात्मक और अमानवीय साधनों का प्रयोग करते हैं। जो ये अमानवीय ढंग से किया गया

कार्य होता है। वह देश का ऐसा वर्ग या समुदाय होता है जो सामाजिक व्यवस्था विरोधी हिंसात्मक साधनों से डरा—धमका के गलत कार्य द्वारा अनुचित ढंग से विनाशकारी कार्य करके आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और जनहानि करवाता है। प्रत्येक आतंकवादी गतिविधियों के पीछे एक आतंकवादी संगठन का मुखिया होता है जो लोगों के अशिक्षा, गरीबी, और बेरोजगारी का फायदा उठाकर वहाँ के लोगों से अपनी दुर्भावनाओं की पूर्ति के लिए धन, शक्ति व धर्म की आड़ में आतंकवादी कार्य करने का दबाब बनाकर उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता है।

प्रारम्भ में आतंकवाद का असर भारतीय रक्षा तथा सुरक्षा पर ही दिखाई देता था, परन्तु आतंकवाद की व्यापकता ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आतंकवाद से लम्बे समय तक प्रभावित होने के कारण भारत के कई राज्यों में व्यवसाय करना व्यापारियों के लिए मुश्किल सा होता जा रहा है इसके साथ ही साथ भारत के ऊपर हमेशा आतंकी हमलों के खतरे के कारण विश्व के कई देश के व्यापारी तथा निवेशक भारतीय बाजारों से दूसरे देश के बाजारों की तरफ रुख करने के लिए विवश हो गये हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अब समय आ गया है कि जब आतंकवाद के विरुद्ध जंग को आर-पार की लड़ाई मानकर खत्म करना आवश्यक हो गया है नहीं तो भारतीय व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति और भयानक हो सकती है।

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये शांति एवं सुरक्षा पहली शर्त है। विगत वर्षों में विश्व के अनेक देशों को सामाजिक एवं जातीय असंतोष एवं आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। वैश्विक आर्थिक नीतियों के कारण इनका प्रभाव लगभग सभी देशों में महसूस किया गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। यद्यपि सब-प्राइम संकट के रूप में अमेरिका से प्रारम्भ होने वाली गहन मंदी का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था ने सफलतापूर्वक किया और इससे बाहर आने के संकेत भी मिलना प्रारम्भ हो गये हैं परन्तु भारत में हुयी आतंकी गतिविधियाँ अभी भी विकास को बाधित कर रही हैं। भारत विगत कई दशकों से आतंकी एवं नक्सली हिंसा की चपेट में है। देश के 608 में से 232 जिले कमोवे आतंकवाद से प्रभावित हैं। पिछले दो दशकों में इन गतिविधियों में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि GDP विकास दर जो 2008 तक 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रही थी। सन् 2009 ई0 एवं सन् 2010 ई0 में 7 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत के मध्य नीचे खिसक गयी है।

आतंकवादी गतिविधियों द्वारा भारतीय व्यापार तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं— तकनीकी विकास जिससे उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को अपने संसाधनों की पुनर्रचना और विकासोन्मुखी कार्यों में उसका आवंटन करना चाहिए। जिससे देश की विकास की दर को बढ़ाया जा सके। सीमावर्ती राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तीय समायोजन पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही ऊर्जा, सड़क, परिवहन तथा उद्योग जैसे बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश के माध्यम से इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अधिक निवेश करके देश की जनसंख्या को स्वस्थ्य तथा शिक्षित बनाया जाना चाहिए। व्यापारियों को निजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने के लिए वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं का निर्माण के लिए प्रेरित करना होगा।

भारत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था आतंकवाद से एक लम्बे समय से प्रभावित होती चली आ रही है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में आतंकवाद सरकार के समक्ष मौजूदा समय की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या बनकर रह गयी है। आतंकवाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है— भ्रष्टाचार। यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि यह दोनों समस्याएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा एक-दूसरे की पूरक के रूप में उभर कर सामने आई हैं। चूंकि आतंकवाद ने आम भारतीय जनमानस से लेकर समस्त प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक तंत्र को अपने चपेट में ले लिया है तथा साथ ही

साथ विश्व स्तर पर भारत की सामरिक, व्यापारिक तथा राजनैतिक ख्याति में गिरावट का प्रमुख कारण बना हुआ है इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध अब आर-पार की लड़ाई लड़ना आवश्यक हो गया है ताकि अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया जा सके तथा देश के विकास को गति प्रदान की जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. खण्डेला, मानचन्द्र (2002), “अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद,” आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
2. सुंदर, नंदिनी (2011), “इन्टर्निंग इनसर्जन्ट पोपूलेशन्स : द बैरीड हिस्ट्रीज ऑफ इण्डियन डेमोक्रेसी,” इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 5, 2011
3. दत्त, रुद्र एण्ड के.पी.एम. सुन्दरम (2010), “भारतीय अर्थव्यवस्था,” एस. चॉद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
4. कुरियन, एन.जे. (2000), “वाइडनिंग रीजनल डिस्पेरिटीज इन इंडिया,” इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 12–18, 2000
5. सिंह, नौनिहाल (1989), “द वर्ल्ड ऑफ टेररिज्म,” साउथ एशियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
6. मारवाह, वेद (1996), “पैथोलोजी ऑफ टेररिज्म इन इण्डिया,” नई दिल्ली।
7. शर्मा, सुरेश के.व.उषा शर्मा (सम्पादक) (1999), “सोसायटी, इकोनोमी एण्ड कल्चर ऑफ कश्मीर,” दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
8. त्रिपाठी, राशि (2010), “आतंकवाद—मानवाधिकार : चुनौती और समाधान,” “बदलते परिदृश्य में नई सहस्राब्दी का भारत,” यादव वीरेन्द्र सिंह (सं), ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
9. कुरुक्षेत्र, 2006।
10. योजना, सितम्बर, 2006।
11. योजना, मई 2008।
12. लल्लन (2003), “राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा,” सारिका ऑफसेट प्रेस, मेरठ।
13. चन्द्र, महेश व वी.के. पुरी (2005), “रीजनल प्लानिंग इन इंडिया,” एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
14. त्रिपाठी, मधुसूदन (2008), “राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद,” ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।